यूट्यूब का सबसे छोटा करोड़पति, वॉलमार्ट भी हुआ मुरीद

न्यूयार्क 7 अगस्त (ए)। दुनिया के हर बच्चे को खिलौने से प्यार होता है। कई बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो कि दूसरों के साथ अपने खिलौनों को साझा भी नहीं करते हैं। लेकिन एक 6 साल का बच्चा खिलौने से खेलते-खेलते करोड़पति बन गया है। इतना ही नहीं अब वॉलमार्ट जैसी कंपनी भी इसकी मुरीद हो गई है। रेयान नाम के इस बच्चे ने पिछले साल यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करके 1 करोड़ डॉलर से ज्यादा की कमाई की थी। यूट्यूब पर रेयान के 6 चैनल हैं जिन पर अपलोड किए गए वीडियों को करीब 1.5 करोड़ से अधिक लोगों ने देखा है। पिछले साल यह बच्चा यूट्यूब पर आंठवां सबसे अधिक कमाई करने वाला शख्स बना था। रेयान तीन साल की उम्र से यूट्यूब पर खिलौनों का रिव्यू करता है। वो प्रत्येक खिलौने को देखकर और उसे समझकर समीक्षा करता है। खिलौने के बारे में वो छोटी से छोटी डिटेल देता है, जिसे देखकर लोग अपने बच्चों के लिए खिलौना खरीदने की सोचते हैं। उसका रिव्यू इतना बढ़िया होता है कि लोग आंखमूंदकर विश्वास भी कर लेते हैं। उसके माता-पिता ने छोटी उम्र को देखते हुए जगह और उपनाम को छुपा रखा है, ताकि मीडिया और पब्लिक की नजर से दूर रहे। अब रेयान ने खुद अपने ब्रांडनेम से खिलौने तैयार किए हैं, जिनको शुरुआत में पूरे अमरीका में बेचा जाएगा। रेयान वर्ल्ड के नाम से वॉलमार्ट के अमरीका में मौजूद 2500 से ज्यादा स्टोर और वेबसाइट पर इनको बेचा जाएगा। अक्टूबर में इस ब्रांड केरक खिलौने अमरीका के प्रत्येक स्टोर पर मिलने लगेंगे।

घोटाले से उबरने में नाकाम पंजाब नैशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक
punjab national bank
शाखा : सैक्टर - 16 डी, चण्डीगढ़
BRANCH : SECTOR - 16 D, CHANDIGARH
ए टी एम
ATM

नई दिल्ली 7 अगस्त (ए)। नीरव मोदी द्वारा किए गए महाघोटाले से प्रभावित पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) को वित्त वर्ष 2018-19 के पहले क्वॉर्टर में भारी नुकसान हुआ है। खबरों के मुताबिक, अप्रैल-जून क्वॉर्टर में पीएनबी को 940 करोड़ रुपये का घाटा झेलना पड़ा। बता दें कि पिछले साल इस क्वॉर्टर में बैंक को 343 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। भारत के चौथे सबसे बड़े बैंक के लिए पिछला कुछ वक्त अच्छा नहीं रहा है। इससे पिछले वित्त वर्ष के आखिरी क्वॉर्टर में बैंक को 13,417 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। यह उसका अबतक का सबसे बड़ा घाटा था। बैंक को लगातार दोनों क्वॉर्टर में घाटा नीरव मोदी द्वारा किए गए घोटाले के बाद हुआ है। नीरव और उनके अंकल मेहुल चोकसी ने मुंबई की एक ब्रांच ब्रेडी हाउस के कुछ कर्मचारियों के साथ मिलकर बैंक को हजारों करोड़ का चूना लगाया। उन्होंने पीएनबी स्टाफ की मदद से फर्जी गारंटी सर्टिफिकेट हासिल करके 13 हजार करोड़ का लोन ले लिया था। यह धांधली पिछले कुछ सालों से चल रही थी, जिसका अब खुलासा हुआ। बैंक के कुछ कर्मचारियों को घोटाले में शामिल होने के लिए पकड़ा गया है, लेकिन मुख्य आरोपी नीरव और चोकसी फिलहाल पकड़ से बाहर हैं।

सिंडिकेट बैंक का पहली तिमाही का घाटा बढ़कर 1,282 करोड़ रुपए हुआ

सिंडिकेटबैंक
SyndicateBank
CARANZALEM BRANCH

नर्द दिल्ली 7 अगस्त (ए)। सार्वजनिक क्षेत्र के सिंडिकेट बैंक को चालू वित्त वर्ष की जून में समाप्त पहली तिमाही में 1,281.77 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। डूबा कर्ज बढने से बैंक का घाटा बढ़ा है। इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में बैंक को 263.19 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में बैंक ने कहा कि तिमाही के दौरान उसकी आय घटकर 5,637.51 करोड़ रुपए रह गई, जो एक साल पहले समान अवधि में 6,171.49 करोड़ रुपए थी। बैंक ने कहा कि समीक्षाधीन तिमाही में उसकी ब्याज आय घटकर 5,484.13 करोड़ रुपए से घटकर 5,257.19 करोड़ रुपए रह गई। इसके अलावा रिजर्व बैंक के पास जमा और अन्य अंतर बैंक कोषों से भी उसकी ब्याज आय घटी है। तिमाही के दौरान बैंक की सकल गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) बढ़कर 12.59 प्रतिशत हो गईं, जो एक साल पहले 9.96 प्रतिशत थीं। मार्च तिमाही में यह 11.53 प्रतिशत के स्तर पर थीं। इस दौरान बैंक का शुद्ध एनपीए भी बढ़कर 6.64 प्रतिशत हो गया। इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में यह 6.27 प्रतिशत तथा मार्च में समाप्त पिछली तिमाही में 6.28 प्रतिशत थी। मूल्य के हिसाब से जून तिमाही के अंत तक बैंक का सकल एनपीए 26,361.52 करोड़ रुपए था, जो एक साल पहले 20,183.85 करोड़ रुपए रहा था। इस दौरान बैंक का शुद्ध एनपीए 12,188.30 करोड़ रुपए से बढ़कर 13,010 करोड़ रुपए पर पहुंच गया।

महाराष्ट्र में तिलहन का रकबा 5 साल में सबसे ज्यादा, सोयाबीन 11% अधिक

मुंबई 7 अगस्त (ए)। चालू खरीफ सीजन में फसलों की कुल बुआई भले ही पिछड़ी नजर आ रही है लेकिन सोयाबीन की बुआई पिछले साल की अपेक्षा करीब 11 फीसदी अधिक हुई है। महाराष्ट्र में तो तिलहन फसलों की बुआई ने पिछले 5 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सबसे ज्यादा बुआई सोयाबीन की हुई है। राज्य में सोयाबीन की बुआई सरकारी अनुमान और सोयाबीन के कुल रकबे को भी पार कर गई है।

खरीफ फसलों की बुआई लगभग पूरी हो चुकी है। मॉनसून की अटपटी चाल की वजह से इस बार खरीफ फसलों की बुआई देश में पिछले साल की अपेक्षा कुछ कम हुई लेकिन तिलहन फसलों की बुआई शानदार दिख रही है। प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में बुआई ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तिलहन फसलों में सोयाबीन की बुआई सबसे ज्यादा हुई है।

केंद्रीय कृषि मंत्रालय और महाराष्ट्र कृषि मंत्रालय के बुआई के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 3 अगस्त तक 37.488 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की बुआई हुई जबकि पिछले साल यानी 2017 में इस समय तक राज्य में 35.449 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की बुआई हुई थी। महाराष्ट्र में 2016 में 36.806 लाख हेक्टेयर, 2015 में 32.198 लाख हेक्टेयर और 2014 में 25.798 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की बुआई हुई थी। राज्य में 3 अगस्त तक का सोयाबीन का औसत रकबा 33.652 लाख हेक्टेयर है जबकि खरीफ सीजन का कुल सामान्य रकबा 35.84 लाख हेक्टेयर है।

महाराष्ट्र कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सोयाबीन की बुआई अनुमान से भी बेहतर हुई है। किसानों को सोयाबीन में फायदा दिख रहा है, सरकार भी किसानों को उन फसलों की तरफ प्रोत्साहित करती है जिनमें किसानों को ज्यादा फायदा हो। सोयाबीन का रकबा बढने की प्रमुख वजह न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी है। चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन का एमएसपी बढ़ाकर 3,399 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है जो पिछले खरीफ सीजन में 3,050 रुपए प्रति क्विंटल था। अधिकारियों का कहना है कि सोयाबीन का रकबा बढने की वजह से तिलहन फसलों का रकबा पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा दिख रहा है।

देश में तिलहन फसलों का रकबा करीब 11 फीसदी अधिक हुआ, जबकि महाराष्ट्र में तिलहन फसलों का रकबा पिछले साल की अपेक्षा करीब छह फीसदी अधिक है। इसके बावजूद राज्य में तिलहन फसलों का रकबा पांच साल में सबसे ज्यादा है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार महाराष्ट्र में 3 अगस्त तक तिलहन फसलों की बुआई का रकबा 39.498 लाख हेक्टेयर हो चुका है। पिछले साल इस समय तक महाराष्ट्र में तिलहन फसलों की बुआई 37.744 लाख हेक्टेयर में हुई थी जबकि राज्य में खरीफ सीजन के दौरान तिलहन फसलों का कुल रकबा 39.20 लाख हेक्टेयर बताया जा रहा है।

देशभर के किसानों ने इस बार सोयाबीन की जमकर बुआई की है। ताजा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 3 अगस्त तक देश में सोयाबीन का रकबा पिछले साल की अपेक्षा 11 फीसदी बढकर 109.50 लाख हेक्टेयर पहुंच गया। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक खरीफ सीजन में सोयाबीन का सामान्य रकबा 112.51 लाख हेक्टेयर है जिसमें से अभी तक औसतन 107.19 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की बुआई होनी चाहिए थी। लेकिन सोयाबीन की बुआई इस रकबे से आगे जा चुकी है। कृषि मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि चालू सीजन में करीब करीब सोयाबीन की बुआई पूरी हो चुकी है। सबसे ज्यादा बुआई मध्य प्रदेश में 53.18 लाख हेक्टेयर में हुई है जबकि पिछले साल इस समय तक राज्य में 47.13 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की बुआई हुई थी।

व्यापारियों ने की 'वन नेशन, वन रजिस्ट्रेशन' की मांग, फिक्की ने किया समर्थन

नई दिल्ली 7 अगस्त (ए)। लघु, कुटीर और मध्यम उद्योग की जीएसटी संबंधी दिक्कतों को दूर करने के लिए गठित मंत्रियों की सब-कमेटी एक्शन मोड में आ गई है। जहां एक ओर वह छोटे-बड़े सभी संगठनों से लघु उद्योगों की सहूलियतों के लिए राय ले रही है, वहीं अलग-अलग सेक्टर के उद्यमी संगठनों से जल्द ही बैठकों का दौर शुरू होने वाला है।

पहली बार जीएसटी पर मंत्री समूह में दिल्ली को जगह मिलने से स्थानीय उद्योग और व्यापार संगठनों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। कमिटी के चेयरमैन वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला और दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया का इस महीने कई संगठनों से मिलने का कार्यक्रम है। सोमवार को एमएसएमई सब-कमिटी को सौंपी सिफारिशों में उद्योग संगठन फिक्की ने वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन पर जोर देते हुए मांग की कि कई राज्यों में काम करने वाले छोटे उद्यमियों को सभी राज्यों में रजिस्ट्रेशन लेने की बाध्यता से मुक्त किया जाए और केवल एक रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करनी चाहिए। फिक्की के प्रेजिडेंट रशेष शाह ने कहा, 'मल्टीपल रजिस्ट्रेशन से सिर्फ उद्यमियों की कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ी है, जबकि इससे रेवेन्यू में कोई योगदान नहीं मिलता। कम से कम एमएसएमई के लिए पूरे देश में सिंगल रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हो और इसके लिए एक खास क्रेडिट मेकनिज़्म कायम किया जाए।'

गाइडलाइंस में हुए बदलाव, बीच में अटकी वन धन योजना

नई दिल्ली 7 अगस्त (ए)। करीब साढ़े तीन महीने पहले छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस महत्वाकांक्षी वन धन योजना को जोरशोर से लॉन्च किया था, अब यह योजना गाइडलाइंस में हुए कई बदलावों के बीच फंसकर रह गई है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक होने के चलते वहां की जनजातीय समुदाय की आजीविका को ध्यान में रखकर यह योजना बनाई गई थी। वन धन योजना को 14 अप्रैल को बीजापुर में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदाय का कौशल विकास करना है। इसके लिए जनजातीय गांवों में मूल्य-संवर्धन केंद्र भी खोले गए। इन केंद्रों को वन धन विकास केंद्र का नाम दिया गया। इसमें पहले अनुसूचित जनजाति के लोगों को यह प्रशिक्षण दिया जाएगा कि वे उन छोटे वन उत्पादों की कीमत कैसे बढ़ाएं, जिन्हें वे इकट्ठा कर मामूली कीमत पर बेचते रहे हैं। वैल्यू एडिशन से उन्हें अपनी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। सूत्रों के अनुसार, यह प्रमुख योजना उचित ग्राउंड वर्क के बाद लॉन्च की गई थी। इसमें स्टेट गवर्नमेंट से भी बातचीत की गई थी और मंत्री समूह ने इस पर हस्ताक्षर भी किए थे। काफी तैयारी के बाद स्कीम की गाइडलाइंस तैयार की गईं। मौजूदा फिस्कल ईयर में पहले चरण में 1500 केंद्र खोले जाने हैं। हालांकि मंत्रिमंडल जून तक गाइडलाइंस को फाइनल टच नहीं दे पाया था। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) और नीति आयोग के कई बार रिमाइंडर देने के बाद जनजातीय मामलों के विभाग की तत्कालीन सचिव लीना नायर ने जून के अंत तक गाइडलाइंस को अंतिम रूप दिया। इन गाइडलाइंस में कुछ ज्यादा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम की परिकल्पना की गई।

यंग टैलेंट को हायर करने खुद को बदल रही कंपनियां

मुंबई 7 अगस्त (ए)। माइनिंग कंपनी वेदांता का इस समय डिजिटल ट्रांसफ़र्मेशन पर जोर है। कंपनी इसके लिए डिजिटल टेक्नॉलजी की अच्छी समझ रखने वाले 50 युवा प्रफेशनल्स की पहचान करने की खातिर एक कैंपेन शुरू करने जा रही है। ये युवा एक डिजिटल इनोवेटर्स ग्रुप बनाएंगे जो कंपनी के डिजिटल प्रॉजेक्ट्स को आगे बढ़ाएगा। ये डिजिटल प्रॉजेक्ट कंपनी की ओवरऑल बिजनस ग्रोथ स्ट्रैटिजी का हिस्सा हैं। वहीं टाटा स्टील ने कई समकालीन और पीपल-फ्रेंडली नीतियों के जरिए कंपनी की पारंपरिक छवि में बदलाव किया है जिससे वो युवा और नेक्स्ट जेनरेशन कर्मचारियों को आकर्षित कर सके। वेदांता और टाटा स्टील के अलावा कई और बड़ी कंपनियां यंग टैलेंट को आकर्षित करने के लिए अपनी पारंपरिक छवि में बदलाव कर रही हैं। इन कंपनियों में टाटा मोटर्स, आरपीजी और महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम भी शामिल है।

टाटा मोटर्स के चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर गजेंद्र चहल ने बताया, पारंपरिक कंपनियों के लिए युवा और नेक्स्ट जेनरेशन को अपनी तरफ आकर्षित करना एक चुनौती है और अगर हम अपनी पॉलिसी, प्रॉसेस और प्रैक्टिस में बदलाव करने के लिए तैयार नहीं है तो उन्हें अपने साथ बनाए रखना उससे भी बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। उन्होंने बताया कि यंग टैलेंट को हायर करना कंपनी की प्राथमिकताओं में है।

नेक्स्ट जेनरेशन टैलेंट को हायर करने के लिए कंपनियां समकालीन, फ्रेंडली पॉलिसी, साझा संस्कृति, नई तकनीक, कंपनी में पारदर्शिता, बेहतर संवाद और डिजिटल रिक्रूटिंग जैसी पहल कर रही हैं। टाटा स्टील ने यंग कर्मचारियों वाले एक टास्कफोर्स का गठन किया है जो ऑर्गनाइज़ेशन के लिए नई स्ट्रैटिजी विकसित करने का काम कर रहा है। उदाहरण के लिए, यह कंपनी के भीतर ही कर्मचारियों को एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में जाने के बहुत से मौके दे रही है। टाटा स्टील के वाइस प्रेजिडेंट (ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट) सुरेश त्रिपाठी ने बताया, टाटा स्टील की छवि एक पारंपरिक कंपनी की है लेकिन हम यंग प्रफेशनल्स को बताना चाहते हैं कि हम उनके सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हैं। अन्य चीजों के अलावा हम बेहतर संवाद और फैक्ट के साथ खुद की रिपोजिशनिंग कर रहे हैं।

यंग जेनरेशन के लिए ये पहल कर रही हैं कंपनियां: कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या में से 42 पर्सेंट संख्या यंग प्रफेशनल्स की है। कंपनी और यंग टैलेंट्स को अपने साथ जोड़ने के लिए स्टील-अ-थॉन, वुमन ऑफ मेटल और माइंड ओवर मैटर जैसी कैंपस गतिविधियां आयोजित कर रही है। टाटा मोटर्स यंग टैलेंट्स की दो मुख्य जरूरतों पर फोकस कर रही है। टाटा का फोकस है कि सबसे पहले इसपर है कि इन युवाओं के साथ जुड़ाव डिजिटल, आसान और तेज हो क्योंकि ये पीढ़ी ऐसे ही बड़ी हुई है और दूसरा ये कि इनके साथ पर्सनलाइज्ड, ह्यूमनाइज्ड और साझा जुड़ाव हो क्योंकि यह पीढ़ी सोशल मीडिया के जरिए एक-दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानने की आदत साथ बड़ी हुई है।

फेसबुक, वॉट्सऐप ब्लॉक करने का रास्ता तलाश रही सरकार

नई दिल्ली 7 अगस्त (ए)। दूरसंचार विभाग (डीओटी) फेक न्यूज और चाइल्ड पॉर्नोग्रफी पर अंकुश के लिए फेसबुक, वॉट्सऐप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जैसे लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप्स को ब्लॉक करने के तरीकों पर विचार कर रहा है। उसने टेलीकॉम कंपनियों और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (आईएसपी) से इसके लिए सुझाव मांगे हैं। इस मामले से वाकिफ सूत्रों ने बताया कि दूरसंचार विभाग फेक न्यूज सहित इन मामलों पर दुनिया की बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों से भी बात करना चाहता है।

अफवाहों से बढ़ी मॉब लिंचिंग की घटनाएं: हाल में फेक न्यूज की वजह से मॉब लिंचिंग की कई घटनाएं हुई हैं और इन्हें लेकर सरकार को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी आलोचना का भी सामना करना पड़ा है। 2019 लोकसभा चुनाव को फेक न्यूज के जरिए प्रभावित करने की भी आशंकाएं जताई जा रही हैं। इन सबके बीच दूरसंचार विभाग ने यह पहल शुरू की है। इस बारे में उसने 18 जुलाई को लिखे एक लेटर में कहा है, 'इंस्टाग्राम, वॉट्सऐप, टेलीग्राम जैसे मोबाइल ऐप्स को इंटरनेट पर कैसे ब्लॉक किया जा सकता है। आपसे इसके संभावित विकल्प बताने की गुजारिश की जाती है।'

यह लेटर भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन इंडिया, आइडिया सेल्युलर के अलावा टेलीकॉम और आईएसपी इंडस्ट्री से जुड़ी संस्थाओं को भेजा गया है। इन ऐप्स को अगर ब्लॉक किया जाता है तो वह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 69ए के तहत किया जाएगा। इस कानून में कंप्यूटर एप्लिकेशन के जरिए दी जा रही इंफॉर्मेशन को ब्लॉक करने के निर्देश अथॉरिटीज को दिए गए हैं। इंडस्ट्री से ऐसे मामलों में राय मांगने के लिए विभाग की तरफ से यह दूसरी चिट्ठी भेजी गई है। पता चला है कि डीओटी ने इसी तरह की एक चिट्ठी 28 जून को भी भेजी थी और उसके बाद 3 अगस्त को उसने रिमाइंडर भेजा था। अभी तक कंपनियों और इंडस्ट्री असोसिएशंस ने दूरसंचार विभाग की चिट्ठी का जवाब नहीं दिया है।

सरकार की चेतावनी: सरकार हाल में फेसबुक के मालिकाना हक वाले वॉट्सऐप को फेक न्यूज पर अंकुश के लिए कई लेटर लिख चुकी है। इसके बाद वॉट्सऐप ने फॉरवर्ड्स की संख्या सीमित करने और न्यूजपेपर ऐड के जरिए जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की है।

आरकॉम की 25,000 करोड़ की परिसंपत्तियां की बिक्री अगस्त के अंत तक संभव

नई दिल्ली 7 अगस्त (ए)। कर्ज के बोझ से दबी दूरसंचार सेवाप्रदाता कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) को उम्मीद है कि वह 25,000 करोड़ रुपए तक की परिसंपत्तियों की बिक्री इस माह के अंत तक संपन्न कर लेगी। इसके अलावा सितंबर अंत तक वह एरिक्सन को 550 करोड़ रुपए चुकाने पर भी सहमत हो गई है ताकि दोनों के बीच के विवाद का निपटान किया जा सके। शेयर बाजार को दी जानकारी में कंपनी ने कहा कि वह 30 सितंबर 2018 से पहले एरिक्सन को 550 करोड़ रुपए चुकाने के लिए सहमत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी तीन अगस्त को दोनों कंपनियों के बीच विवाद निपटाने की इस प्रक्रिया को मंजूर कर लिया था। उल्लेखनीय है कि दोनों कंपनियों के बीच 2014 में एक सात साल का समझौता हुआ था।

इसमें एरिक्सन को देशभर में आरकॉम के दूरसंचार नेटवर्क के परिचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई थी। एरिक्सन का आरोप था कि आरकॉम ने उसके 1,500 करोड़ रुपये का बकाया नहीं चुकाया है और वह इस मामले को लेकर राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण में ले गई थी। इस संबंध में अधिकरण के 30 मई के फैसले पर गौर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला दिया। इसके अनुसार एरिक्सन अपने 1500 करोड़ रुपए के बकाया को 550 करोड़ रुपए में निपटाने के लिए तैयार हो गई।

सैमसंग ने फिर सस्ते किए टीवी, कीमतों में 15 फीसदी की कटौती

मुंबई 7 अगस्त (ए)। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने बाजार में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए त्योहारी सीजन से पहले ही टीवी के टॉप मॉडल सस्ते कर दिए हैं। मोबाइल और टेलीविजन बाजार के प्रमुख दिग्गज सैमसंग ने यह कदम तब उठाया जब इंडस्ट्री कीमतें बढ़ाने पर विचार कर रही है। कंपनी ने दो महीने में दूसरी बार कीमतों में कटौती की है।

2 बार कीमतों में कटौती: कंपनी ने 32 इंच से 43 इंच की स्क्रीन साइज वाले टीवी की कीमतों में लगभग 5 फीसदी की कटौती की है, जिससे यह 1,000 रुपए से 2,500 रुपए तक सस्ते हो गए हैं।75 इंच के टीवी की कीमतों में 15 फीसदी की कटौती की गई है। पिछली जून में सैमसंग ने 10-20 फीसदी की कटौती की थी। इंडस्ट्री सूत्रों का कहना है कि यह पहली बार है कि सैमसंग ने दो महीने से भी कम समय में नए मॉडल की कीमतें कम कर दी है। उन्होंने कहा कि सैमसंग का लक्ष्य ऑनलाइन ब्रांड जैसे श्योमी, बीपीएल, वीयू और कोडेक से आगे निकलना है।

43 इंच के टीवी सस्ते: 43 इंच के टीवी की कीमत 37,000 रुपए हो गई है। हालांकि यह मॉडल टीसीएल और थॉमसन से काफी महंगा है लेकिन सैमसंग, एलजी, सोनी और पैनासोनिक को उम्मीद है कि ब्रांड मूल्य और सर्विस को देखकर लोग उनके टीवी खरीदने में पहल करेंगे।सैमसंग के इस कदम से उनके प्रतिद्वंद्वी एलजी, पैनासोनिक और सोनी कीमतों में कटौती करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। हालांकि पैनासोनिक ने 40 इंच से ऊपर के कुछ मॉडलों की कीमतें कम कर दी है। भारतीय टीवी बाजार में सैमसंग की लगभग 30 फीसदी हिस्सेदारी है।